



राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड

राज्य मुख्यालय

जवाहरलाल नेहरू मार्ग, बजाज नगर, जयपुर - 302015 (राज.)

टेलीफोन नं. - 0141-2706830, 2941098 ई-मेल - rajscoutguide@yahoo.com



खुली प्रतियोगी बोली (खुली निविदा)

भारत स्काउट व गाइड, राष्ट्रीय मुख्यालय, नई दिल्ली एवं राज्य मुख्यालय, जयपुर के तत्वाधान में ग्राम नीमली ब्राह्मणान, तहसील रोहट, जिला-पाली - 306421 (राजस्थान) में स्थित दिल्ली मुम्बई इण्डस्ट्रीयल कॉरीडोर पर आयोजित होने वाली 18वीं राष्ट्रीय स्काउट/गाइड जम्बूरी, दिनांक 04 से 10.01.2023 तक में एडवेंचर बेस हेतु रस्से, रस्सी व अन्य सामग्री (क्रय हेतु) आपूर्ति हेतु द्वि-प्रकर्म बोली यथा तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड प्रक्रिया के अन्तर्गत निम्नानुसार निविदा आमंत्रित की जाती है :-

1	कार्य का विवरण/सन्दर्भ	एडवेंचर बेस हेतु रस्से, रस्सी व अन्य सामग्री (क्रय हेतु)
2	अनुमानित लागत (रूपये में)	4,30,000 / -
3	बोली शुल्क (रूपये में)	500 / - (डिमाण्ड ड्राफ्ट)
4	बोली प्रतिभूति राशि-दो प्रतिशत (रूपये में)	8,600 / - (डिमाण्ड ड्राफ्ट)
5	बोली दस्तावेज बिक्री की तिथि एवं समय	दिनांक 10.09.2022 समय प्रातः 11.00 बजे से
6	प्री-बिड बैठक की तिथि, समय व स्थान	दिनांक 17.09.2022 समय दोपहर 03.00 बजे राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड, राज्य मुख्यालय, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, बजाज नगर, जयपुर
7	शुद्धिपत्र अपलोड करने की तिथि व समय	दिनांक 19.09.2022 समय सांय 06.00 बजे तक
8	प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षरित बोली दस्तावेज Offline जमा कराने की अन्तिम तिथि एवं समय	दिनांक 20.09.2022 समय प्रातः 11.00 बजे से दिनांक 23.09.2022 समय दोपहर 12.00 बजे तक।
9	तकनीकी बिड खोले जाने की तिथि एवं समय	दिनांक 23.09.2022 को दोपहर 03.00 बजे
10	वित्तीय बिड खोले जाने की तिथि एवं समय	तकनीकी रूप से सफल बोलीदाताओं को वित्तीय बिड खोलने के सम्बन्ध में सूचना पृथक से प्रेषित की जायेगी।
11	निविदा प्रपत्र सामने दर्शायी वैबसाईट से भी डाउनलोड किया जा सकता है।	http://sppp.rajasthan.gov.in https://rajscoutguide.org
12	अनुबन्ध अवधि	वित्तीय वर्ष 2022-23 (31 मार्च, 2023 तक) लॉकडाउन की स्थिति में तत्समय जारी निर्देश प्रभावी होंगे।

दिनांक :

राज्य सचिव
जयपुर

P. Chavhan
राज्य सचिव
राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड
राज्य मुख्यालय, जयपुर

17

19. टर्नओवर विगत तीन वर्षों का (छांयाप्रति संलग्न करें)

- 2019-20 :
- 2020-21 :
- 2021-22 :

20. अन्तिम त्रैमास (अप्रैल, 2022 से जून, 2022 तक) की जी.एस.टी. रिटर्न की प्रति (GSTR-1/GSTR-3B/Other)

(नोट - कृपया संलग्न अनुलग्नक - एफ (चैक लिस्ट) की समस्त पूर्ति कर निविदा प्रस्तुत करें।)

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर निविदादाता

मय मोहर

फर्म का नाम

फर्म के पत्र व्यवहार का पूरा पता

टेलीफोन नम्बर


प. चेलिका
सहस्रमन राज्य सेवा स्टाफ 6 मई
राज्य सेवा, पटना

3/17



राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड

राज्य मुख्यालय

जवाहरलाल नेहरू मार्ग, बजाज नगर, जयपुर – 302015 (राज.)

टेलीफोन नं. – 0141-2706830, 2941098 ई-मेल – rajscoutguide@yahoo.com



भारत स्काउट व गाइड, राष्ट्रीय मुख्यालय, नई दिल्ली एवं राज्य मुख्यालय, जयपुर के तत्वाधान में ग्राम नीमली ब्राह्मणान, तहसील रोहट, जिला-पाली – 306421 (राजस्थान) में स्थित दिल्ली मुम्बई इण्डस्ट्रीयल कॉरीडोर पर आयोजित होने वाली 18वीं राष्ट्रीय स्काउट/गाइड जम्बूरी में एडवेंचर बेस हेतु रस्से, रस्सी व अन्य सामग्री (क्रय हेतु) हेतु निविदा के उपनियम एवं शर्तें :-

निविदादाता को निविदा देते समय इन शर्तों को अत्यन्त ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए क्योंकि इन शर्तों का निविदादाता द्वारा पालन करना अत्यावश्यक होगा :-

1. निविदा सीलबन्द लिफाफे में तकनीकी एवं वित्तीय पृथक-पृथक देनी होगी। प्रथम लिफाफा निविदादाता की तकनीकी योग्यता एवं निविदा प्रपत्र के सम्बन्ध में होगा। द्वितीय लिफाफा निविदादाता की वित्तीय प्रस्ताव सम्बन्धी कार्य की दरों से सम्बन्धित होगा। जिस पर क्रमशः “एडवेंचर बेस हेतु रस्से, रस्सी व अन्य सामग्री क्रय हेतु (तकनीकी निविदा)” व “एडवेंचर बेस हेतु रस्से, रस्सी व अन्य सामग्री क्रय हेतु (वित्तीय निविदा)” स्पष्ट एवं मोटे अक्षरों में लिखा जायेगा। ये दोनों लिफाफे एक बड़े लिफाफे में बन्द करके प्रस्तुत करने होंगे।
2. “वित्तीय निविदा” के लिफाफे में मात्र “वित्तीय दरें” ही लिखी जायेंगी। इसके अतिरिक्त समस्त दस्तावेज इत्यादि तकनीकी निविदा के लिफाफे में रखे जाने चाहिए।
3. यदि किसी निविदादाता द्वारा तकनीकी निविदा के लिफाफे में वित्तीय निविदा भी डाल दी जायेगी तो उस निविदादाता की दोनों निविदाएँ रद्द कर दी जायेगी।
4. तकनीकी बोली एवं वित्तीय बोली के लिफाफे पर निविदादाता द्वारा अपनी फर्म का पूर्ण स्पष्ट पता एवं फोन/मोबाइल नम्बर आवश्यक रूप से लिखा जाना चाहिए। व्यक्तिगत निविदा मान्य नहीं होगी।
5. सर्वप्रथम तकनीकी निविदा वाला लिफाफा खोला जायेगा, तकनीकी योग्यता रखने वाली फर्मों द्वारा दी गई जानकारी का सत्यापन आवश्यकता होने पर समिति द्वारा किया जा सकता है। निरीक्षण की स्थिति में यदि कोई तथ्य गलत पाया जाता है तो उस फर्म की तकनीकी दर निविदा को रद्द कर दिया जायेगा।
6. तकनीकी निविदा में सफल निविदादाता की ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी। तकनीकी बिड के मुल्यांकन में योग्य पाये गये समान प्रकृति के कार्य करने वाली अनुभवी व इच्छुक पंजीकृत फर्मों/कम्पनी को वित्तीय बिड खोलने के सम्बन्ध में पृथक से सूचना दी जाएगी। यदि किसी कारणवश उस दिन अवकाश रहता है तो अगले कार्य दिवस को उसी समय व स्थान पर सम्बन्धित कार्यवाही की जावेगी।
7. निविदा फार्म वेबसाइट से डाउनलोड कर प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में भी निविदादाता द्वारा निविदा के साथ निविदा शुल्क राशि रु. 500/- का बैंक ड्राफ्ट जो “राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड जयपुर” के पक्ष में देय हो, जमा कराना आवश्यक होगा।
8. खुली प्रतियोगी बोली (खुली निविदा) के क्रम संख्या 3 व क्रम संख्या 4 में क्रमशः दर्शाई गई बोली शुल्क राशि रु. 500/- व बोली प्रतिभूति राशि रु. (दो प्रतिशत) 8,600/- का डी.डी. (नकद/चैक स्वीकार्य नहीं) “राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड जयपुर” के पक्ष में जयपुर में भुगतान योग्य बनवाना होगा। बोलीदाता द्वारा बोली शुल्क, बोली प्रतिभूति शुल्क तथा निविदादाता द्वारा घोषणा (एस.आर. प्रारूप – 11) निविदा के साथ, निर्धारित दिनांक एवं समय तक इस कार्यालय में जमा करवाये जाने आवश्यक है अन्यथा सम्बन्धित निविदादाता के प्रस्ताव अस्वीकार कर दिये जावेंगे।
9. निविदादाता को विगत तीन वर्षों में से किसी एक वित्तीय वर्ष में निविदत्त अनुमानित लागत के 80 प्रतिशत के बराबर निविदा से सम्बन्धित सरकारी/अर्द्धसरकारी/राजकीय उपक्रमों/राजकीय संस्थानों/निगमों/अन्य विभागों में सप्लाई/कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। इस हेतु कार्य आदेशों/अनुभव प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रतियां संलग्न करनी होगी, अन्यथा वह तकनीकी/वित्तीय मापदण्ड के आधार पर अयोग्य माना जायेगा व उसके वित्तीय प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा। इसके प्रमाण के रूप में सम्बन्धित संस्थानों के अनुभव/कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र साथ ही पिछले तीन वर्षों (वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22) का सी.ए. द्वारा प्रमाणित दस्तावेज (प्रमाण-पत्र) जिसमें इस व्यवसाय से सम्बन्धित आय का उल्लेख हो, संलग्न करना होगा।

P. S. Jain

राज्य सचिव
राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड
राज्य मुख्यालय, जयपुर

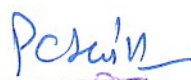
4/17

10. निविदादाता को नवीनतम कर बकाया नहीं के प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि अथवा गत त्रैमास (अप्रैल, 2022 से जून, 2022 तक) की जी.एस.टी. रिटर्न की प्रति (GSTR-1/GSTR-3B/Other) संलग्न करनी आवश्यक होगी।
11. निविदा प्रपत्र में दरें स्याही अथवा टंकण द्वारा भरी जावे जो सुपाठ्य हो। पैन्सिल से भरी हुई निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।
12. दरें अंको एवं शब्दों में अंकित करें, दरों में परिवर्तन की दशा में निविदादाता दिनांक सहित लघुहस्ताक्षर करें। किसी भी प्रकार की कटिंग/ओवरराईटिंग नहीं करें तथा निविदादाता द्वारा निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर मय मोहर किये जावें।
13. निविदादाता को निविदा संलग्न निर्धारित प्रपत्र में ही प्रस्तुत करनी होगी। अन्य कोई प्रपत्र स्वीकार नहीं होगा।
14. यदि कोई साझेदारी फर्म बोली लगाती है तो बोलीदाता फर्म को बोली लगाते समय रजिस्टर्ड साझेदारी संलेख प्रस्तुत/अपलोड करनी आवश्यक होगी, अन्यथा वह निविदादाता फर्म बोली में भाग नहीं ले सकेगी। व्यक्ति/संस्था/फर्म द्वारा प्रस्तुत बोलियों पर क्रय/निविदा समिति द्वारा विचार किया जायेगा। इस सम्बन्ध में क्रय/निविदा समिति का निर्णय अन्तिम होगा।
15. बोली खोलने की तिथि को किसी कारणवश यदि समस्त बोलियां नहीं खोली जा सकती हैं तो उसके अगले कार्यदिवस को बोलियां खोलने का कार्य जारी रखा जायेगा।
16. तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा पर निविदादाता द्वारा अपनी फर्म का पूर्ण स्पष्ट पता एवं फोन/मोबाइल नम्बर आवश्यक रूप से लिखा जाना चाहिए।
17. तकनीकी योग्यता रखने वाली फर्मों द्वारा दी गई जानकारी का सत्यापन आवश्यकता होने पर क्रय/निविदा समिति द्वारा किया जा सकता है। निरीक्षण की स्थिति में यदि कोई तथ्य गलत पाया जाता है तो उस फर्म की तकनीकी निविदा को रद्द कर दिया जायेगा।
18. यदि निविदादाता सत्यनिष्ठा संहिता (Code of integrity) एवं हित का विरोध (Conflict of interest) सम्बन्धित प्रावधानों का उल्लंघन करता है या करता हुआ पाया जाता है तो राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 82 के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
19. निर्धारित तिथि को बोली खोलने के उपरान्त/पश्चात् प्रस्तावित दर पर कार्य में असमर्थता या दरों में संशोधन स्वीकार्य नहीं होगा। ऐसा होने पर बोली प्रतिभूति राशि जब्त/शास्ति एवं आगामी बोली से वंचित/अयोग्य इत्यादि हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
20. बोली प्रतिभूति राशि जमा कराने की स्थिति में बोली प्रतिभूति राशि का निम्न परिस्थितिओं में पूर्ण या आंशिक रूप से समपहरण/जब्त किया जा सकेगा :-
 - जब निविदादाता द्वारा निविदा के किन्हीं निबंधनों और शर्तों का उलघन किया गया हो।
 - जब निविदादाता निविदा खोलने के पश्चात्, किन्तु निविदा स्वीकृति से पूर्व निविदा वापिस लेता है या प्रस्ताव को उपान्तरित कर देता है।
 - जब निविदादाता निर्दिष्ट समय के भीतर विहित करार व आदेश को सम्पादित नहीं करता है।
 - जब दर स्वीकृति पश्चात् निविदादाता सुरक्षा राशि जमा नहीं कराता है।
 - बोली प्रतिभूति राशि का समपहरण/जब्त करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जायेगा। इस सम्बन्ध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।
21. द्वितीय एवं तृतीय निम्नतम निविदादाताओं की बोली प्रतिभूति राशि सफल निविदादाता को कार्यादेश जारी करने के एक माह पश्चात् लौटाई जायेगी, शेष निविदादाताओं की बोली प्रतिभूति राशि निविदा स्वीकृति के निर्णय के बाद शीघ्र लौटा दी जायेगी।
22. निविदा केवल उन्हीं फर्मों द्वारा दी जानी चाहिए जो इस क्षेत्र के वास्तविक व्यवसायी हैं, फर्म इस क्षेत्र में अनुभव रखने वाली होनी चाहिए। निविदादाता किसी भी सरकारी/अर्द्धसरकारी/राजकीय उपक्रमों/राजकीय संस्थानों/गैर राजकीय संस्थानों में ब्लैक लिस्ट नहीं हो, अतः इस हेतु निविदादाता को एस.आर. प्ररूप-11 (संलग्न) में राशि रु. 50/- के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
23. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये पूर्ण अथवा आंशिक रूप से स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।
24. निविदा की शर्तों के अतिरिक्त कोई अन्य शर्त (शर्तयुक्त/सशर्त निविदा) स्वीकार नहीं होगी। बोलीदाता का/उसके प्रतिनिधी की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता होगी।


 राज्य सचिव
 राजस्थान राज्य शासक शाखा व महसुस
 राज्य मुख्यालय, जयपुर

5
 17

25. निविदादाता द्वारा संलग्न वर्णित दरें/दर-अनुबन्ध दिनांक 31.03.2023 तक अथवा विशेष परिस्थिति में जम्बूरी की तिथियों में परिवर्तन होने पर जम्बूरी अवधि तक के लिए मान्य होगी/किया जायेगा। निविदादाता को उक्त अवधि तक इन दरों पर ही कार्य करना होगा। इस अवधि को पारस्परिक सहमति के आधार पर आगे के लिए बढ़ाया जा सकेगा।
26. निविदादाता निविदा अथवा उसके किसी भी सारवान भाग को अन्य किसी व्यक्ति/एजेन्सी को सबलेट नहीं करेगा।
27. सक्षम अधिकारी को निविदादाता द्वारा दी गई आईटमवाइज दरें अथवा एक मुश्त दरें या दोनों रूप में स्वीकार करने का अधिकार होगा। आंशिक कार्य हेतु निविदा स्वीकार करने/नहीं करने का अधिकार सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।
28. निरीक्षण/परिक्षण के दौरान सेवा/सामग्री/प्रदाय का जो हिस्सा निर्धारित स्तर का नहीं होगा। उसे रद्द करने का अधिकार सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।
29. सक्षम अधिकारी को किसी भी निविदा को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की निविदा नहीं है, को स्वीकार करने का अथवा बिना कोई कारण बताये किसी भी निविदा/उसके किसी भी भाग को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
30. सफल निविदादाता को कार्यादेश प्राप्त हो जाने के 07 दिवस की अवधि के भीतर कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि (बोली राशि का 2.5 प्रतिशत) जमा करवाकर अनुबन्ध सम्पादित करना होगा, जिसमें बोली प्रतिभूति राशि का समायोजन किया जा सकेगा। कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का डी.डी. "राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड जयपुर" के पक्ष में जयपुर में भुगतान योग्य बनवाना होगा। इस कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का निम्नलिखित प्रकरणों में पूर्णतः या अंशतः समपहरण किया जा सकेगा।
 - जब निविदादाता द्वारा संविदा के किन्ही निबंधनो ओर शर्तों का उलघन किया गया हो।
 - जब निविदादाता संतोषप्रद रूप से निर्धारित अवधि में पूर्ण सेवा/सामग्री/प्रदाय करने में असफल रहता है।
 - राशि का समपहरण करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जायेगा। इस सम्बन्ध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।
31. कार्य सम्पादन प्रतिभूति/सुरक्षा राशि पर इस कार्यालय द्वारा किसी भी प्रकार के ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।
32. सफल निविदादाता को निविदा स्वीकृत एवं कार्यादेश प्राप्त हो जाने के 07 दिवस की अवधि के भीतर राशि रु. 500/-के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पर एस.आर. प्रारूप 17 में एक करार पत्र जमा कराना होगा। करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने के व्यय का भुगतान निविदादाता द्वारा किया जाएगा तथा इस कार्यालय द्वारा उस करार की एक निष्पादित स्टाम्पशुदा प्रतिपड़त (छांयाप्रति) निविदादाता को निःशुल्क दी जाएगी।
33. घोषणा पत्र व अनुबन्ध पत्र के निष्पादन में देय स्टाम्प-रजिस्ट्री शुल्क एवं जो भी कानूनी व्यय होगा, उन समस्त व्यय की राशि अदा करने का दायित्व सफल निविदादाता का होगा।
34. निर्धारित अवधि में सेवा/सामग्री/प्रदाय की आपूर्ति नहीं करने की स्थिति में, सुरक्षा राशि जब्त की जा सकेगी अथवा अन्य व्यवस्था, आवंटित कार्य को बीच में छोड़ने पर बाजार से उच्च दरों पर कराये जाने पर जो हानि होगी वह निविदादाता की सुरक्षा राशि में से समायोजित की जा सकेगी।
35. यदि निविदा सूचना में अथवा आदेशित मात्रा में, जैसी भी स्थिति हो दर्शित मात्रा से कम या अधिक के आदेश दे दिये जाते हैं, तब भी निविदादाता सेवा/सामग्री/प्रदाय हेतु आबद्ध होगा। निविदादाता मुवावजा हेतु किसी भी दावे का हकदार नहीं होगा।
36. आपूर्ति की जाने वाली सामग्री की दरें सभी प्रकार के करों सहित अंकित करें।
37. नियमानुसार टी.डी.एस./जी.एस.टी. टी.डी.एस. एवं अन्य कटौती की जायेगी जिसके लिए पैन नम्बर/जी.एस.टी. नम्बर की प्रति निविदा के साथ आवश्यक रूप से संलग्न करें।
38. निविदा में वर्णित सेवा/सामग्री/प्रदाय सक्षम अधिकारी अथवा उनके किसी प्रतिनिधि की मांग के अनुसार निर्देशित दिनांक, समय व स्थान पर देना होगा।
39. निविदादाता द्वारा शर्तों के उल्लंघन करने/कार्य सन्तोषजनक न होने की स्थिति में अनुपातिक कटौती के सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी का निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा।


 राज्य सचिव
 राजस्थान राज्य आपूर्ति निगम व राज्य
 आपूर्ति निगम, जयपुर

6
 17

40. कार्यदेश/अनुबन्ध में वर्णित कार्य सुचारु व सन्तोषजनक रूप से पूरा न करने पर यदि आवश्यक समझा गया तो कार्य निविदादाता के हर्ज-खर्च पर अन्य साधन से कार्य करवाया जायेगा तथा यदि इस व्यवस्था पर कोई अतिरिक्त व्यय इस कार्यालय को वहन करना पडा तो वह राशि सफल निविदादाता से वसूली योग्य होगी।
41. एडवेंचर बेस हेतु रस्से, रस्सी व अन्य सामग्री (क्रय हेतु) सम्बन्धी कार्य के सम्बन्ध में निर्धारित विशिष्ट शर्तें 'परिशिष्ट-1' व जो इन शर्तों के साथ पृथक से संलग्न हैं, इन शर्तों का भाग होंगी।
42. वर्तमान में प्रभावी किसी भी राजकीय कानून/नियम के समस्त नियमों आदि की पालना का पूर्ण दायित्व भी निविदादाता का होगा। यह कार्यालय इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।
43. निविदादाता को राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों की भी पालना करनी आवश्यक होगी।
44. सभी विवादों/विधिक कार्यवाही यदि संस्थित की जानी आवश्यक हो तो न्यायिक क्षेत्र, जयपुर (राज.) ही रहेगा।
45. भुगतान :- निविदादाता को सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार गतिविधियों/शिविरों की समाप्ति के पंचम कार्यदिवस तक बिल मय प्रमाणिकरण सहित दो प्रतियों में तैयार कर सम्बन्धित प्रभारी के माध्यम से इस कार्यालय को अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा। इस बिल का भुगतान सामान्य प्रक्रियानुसार ऑनलाइन/नेफ्ट/रेखांकित चैक/ऑनलाईन द्वारा किया जाएगा।
46. उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त अन्य परिस्थितियों में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम खण्ड-द्वितीय में वर्णित एस.आर. प्ररूप - 14, 15, 16, 17, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2012 व 2013, वित्त (जीएण्डटी) विभाग की अधिसूचना दिनांक 18.12.2020 (हिन्दी अनुवाद दिनांक 15.02.2021) एवं वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के परिपत्र दिनांक 23.12.2020 में दी गई समस्त शर्तें/प्रावधान यथावत लागू होंगे।
47. कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन की स्थिति में तत्समय जारी निर्देश प्रभावी होंगे।

मैंने/हमने उपरोक्त अनुसार वर्णित शर्तों को भली भाँति पढ लिया एवं समझ लिया है। मैं/हम उपरोक्त वर्णित समस्त शर्तों की पूर्ण पालना के साथ हमारी फर्म द्वारा दी गई दरों पर कार्य करने के लिए सहमत हैं।

स्थान :
दिनांक :

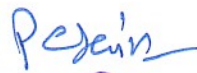

राजेश सचिव
राजस्थान राज्य राजस्व एकाइ व ग्राहक
सहायक मुख्यमंत्री, जयपुर

हस्ताक्षर निविदादाता
मय मोहर

फर्म का नाम
फर्म के पत्र व्यवहार का पूरा पता
.....
.....
टेलीफोन नम्बर

एडवेंचर बेस हेतु रस्से, रस्सी व अन्य सामग्री (क्रय हेतु)
“विशिष्ट शर्तें”

1. एफ.ओ.आर. जम्बूरी स्थल - ग्राम नीमली ब्राह्मणान, तहसील रोहट, जिला-पाली - 306421 (राजस्थान) में स्थित दिल्ली मुम्बई इण्डस्ट्रीयल कॉरीडोर पर निर्धारित अवधि (कार्यादेश के अनुसार) में देनी होगी। इस हेतु पृथक से किसी भी प्रकार का भुगतान देय नहीं होगा।
2. तत्काल आवश्यकता की स्थिति में भी अधिकृत प्राधिकारियों के लिखित/मौखिक आदेशानुसार सामग्री उपलब्ध करवानी आवश्यक होगी।
3. निविदादाता को पूर्व में किए गये राष्ट्रीय स्काउट/गाइड जम्बूरी से संबंधित अथवा इस प्रकार के राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय कार्यक्रम, महोत्सव, मेला इत्यादि जैसे वृहद् कार्यक्रम करवाने का कार्यानुभव व ज्ञान होना चाहिए, को निविदा में प्राथमिकता प्रदान की जावेगी। इस हेतु निविदादाता को पूर्व में किये गये इन आयोजनों से संबंधित कार्य का कार्यादेश/अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।
4. निविदादाता निविदा से सम्बन्धित सामग्री की सुरक्षा एफ.ओ.आर. होने तक स्वयं करेगा, यह विभाग प्राकृतिक आपदा, आगजनी, चोरी, हानि, नुकसान एवं सभी सामान को लाने ले जाने पर टूट-फूट आदि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
5. आदेशित कार्य/व्यवस्था को करते समय यदि निविदादाता के किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है या कर्मचारी किसी भी रूप में दुर्घटना ग्रस्त/अपंग हो जाता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी एवं उसके लिए मुआवजा आदि लेने का भार निविदादाता द्वारा वहन किया जायेगा। यह कार्यालय इसके लिए किसी भी प्रकार से मददगार एवं जिम्मेदार नहीं होगा।
6. निविदादाता अपने कर्मचारियों के चाल-चलन, चरित्र इत्यादि के सम्बन्ध में स्वयं निविदादाता जिम्मेदार होगा। अनाधिकृत व्यक्ति का परिसर में प्रवेश वर्जित रहेगा।
7. निविदादाता को उक्त कार्य शासकीय नियमानुसार करना होगा तथा राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों की भी पालना करनी होगी।
8. जम्बूरी स्थल पर प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा। अतः इसका विशेष ध्यान रखा जावे।
9. विवादास्पद मदों में राशि का 10 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक को रोका जायेगा तथा उस विवाद का निपटारा का हो जाने पर उसका भुगतान किया जायेगा।
10. कार्य/सामग्री आपूर्ति की मात्रा में कमी/वृद्धि पर आवश्यकतानुसार कार्यादेश देने का अधिकार सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा। निविदा की शर्तों के अतिरिक्त कोई अन्य शर्तें स्वीकार नहीं होंगी।
11. निविदा से सम्बन्धित सामग्री कटी-फटी नहीं होनी चाहिए। समस्त सामग्री अच्छी हालत में साफ सुथरी हो, मैली गन्दी ना हो। खराब सामग्री स्वीकार नहीं होगी।
12. निविदादाता द्वारा निविदा में दी गई सामग्री स्पेसिफिकेशन के आधार पर नहीं होने पर सामग्री स्वीकार नहीं की जायेंगे। समस्त सामग्री निर्धारण मापदण्डानुसार व दिये गये पेरामीटर के अनुसार होनी आवश्यक है।
13. सामग्री आपूर्ति करने के दौरान ट्रान्सपोर्ट में सामग्री खराब हो जाने, भीग जाने, गीली हो जाने अथवा टूट फुट हो जाने की स्थिति में खराब सामग्री की श्रेणी में कोई अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा, और इस एवज में अच्छी और गुणवत्तापूर्ण सामग्री की आपूर्ति अनुबन्धकर्ता द्वारा की जावेगी।



राज्य सचिव

राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड

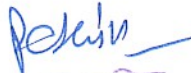
राज्य मुख्यालय, जयपुर

8
17

14. तकनीकी निविदा में सफल निविदादाता को क्रय की जाने वाली समस्त सामग्री का नमूना कार्यालय में जमा करवाना आवश्यक होगा। वित्तीय निविदा में सफल निविदादाता एल-1 से एल-3 को अपनी सामग्री का निर्देशानुसार प्रस्तुतीकरण देना आवश्यक होगा।
15. तार/ईमेल/फैक्स द्वारा प्राप्त निविदा मान्य नहीं होगी।

स्थान :

दिनांक :


राज्य सचिव
राजस्थान राज्य भारत स्काउट्स व गाइड्स
राज्य मुख्यालय, जयपुर

हस्ताक्षर निविदादाता
मय मोहर

फर्म का नाम

फर्म के पत्र व्यवहार का पूरा पता

.....

टेलीफोन नम्बर

9/17

“निविदादाता द्वारा घोषणा”

उपरोक्त समस्त जानकारी/शर्तों का मैंने/हमने अच्छी तरह अध्ययन कर लिया है। मुझे/हमें यह भी स्वीकार है कि राज्य सचिव, राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड, राज्य मुख्यालय, जयपुर का निर्णय हमारे लिये मान्य होगा। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि मेरी/हमारी फर्म उक्त कार्य हेतु रजिस्टर्ड है तथा फर्म द्वारा वास्तव में बिड में चाहा गया व्यवसाय किया जाता है तथा वांछित मशीन/उपकरण/तकनीकी अनुभव व तकनीकी कर्मचारी आदि उपलब्ध है। राज्य सरकार/बोर्ड/विश्वविद्यालय/स्वायत्तशासी संस्थान/निगम/बैंक आदि के द्वारा मेरी/हमारी फर्म को ब्लैक लिस्ट नहीं किया हुआ है। प्रतिकस्वरूप निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर (मयसील) कर दिये हैं।

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने जिन मालों/सामानों/उपकरणों के लिए निविदा दी है, उनका/उनके/ मैं/हम बोनाफाइड विनिर्माता/थोक विक्रेता/सोल वितरक/प्राधिकृत डीलर/डीलर/सोल विक्रय/विपणन एजेंट हूँ/हैं।

यदि ये घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समपहत कर लिया जा सकेगा तथा निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

नोट :-

1. यह घोषणा निविदादाताओं द्वारा तकनीकी बिड के साथ प्रस्तुत की जानी आवश्यक है।
2. इस घोषणा को राशि रु. 50/- के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पर प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

स्थान :

दिनांक :


राज्य सचिव
राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड
राज्य मुख्यालय, जयपुर

हस्ताक्षर निविदादाता

मय मोहर

फर्म का नाम

फर्म के पत्र व्यवहार का पूरा पता

.....

.....

टेलीफोन नम्बर

10
17

Annexure A : Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall-

- (a) Not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
- (b) Not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
- (c) Not indulge in any collusion, Bid rigging or anticompetitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
- (d) Not misuse any information shared between the procuring entity and the bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
- (e) Not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
- (f) Not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
- (g) Disclose conflict of interest, if any; and
- (h) Disclose any previous transgressions with any entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

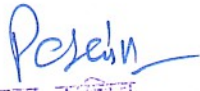
Conflict of interest.-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

(i) A bidder may be considered to be in conflict of interest with one or more parties in the bidding process if, including but not limited to:

- (a) Have controlling partners/shareholders in common; or
- (b) Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
- (c) Have the same legal representative for purposes of the bid; or
- (d) have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the bid of another bidder, or influence the decisions of the procuring Entity regarding the bidding process; or
- (e) The bidder participates in more than one bid in a bidding process. Participation by a bidder in more than one bid will result in the disqualification of all bids in which the bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a bidder, in more than one bid; or
- (f) the bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the goods, Works or services that are the subject of the Bid; or
- (g) Bidder or any of its affiliates has been hired (or proposed to be hired) by the procuring entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.


राज्य सचिव
राजस्थान राज्य भारत स्काउट्स एंड गाइड्स
राज्य मुख्यालय, जयपुर

**Bidder Signature
With Stamp**

11/17

Annexure B : Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted tofor procurement ofin response to their Notice inviting Bids No
Dated I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 that :

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entry;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the union and the state government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date :

Place :

Signature of bidder

Name :

Designation :

Address :


राजस्थान राज्य शासक सचिव
राजस्थान राज्य शासक सचिव
राजस्थान राज्य शासक सचिव

**Bidder Signature
With Stamp**

12
17

Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is State Secretary, RSBS&G, Jaipur

The designation and address of the Second Appellate Authority is State Chief Commissioner, RSBS&G, Jaipur

1. Filing an appeal

if any bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the procuring entity is in contravention to the provisions of the Act or the rules or the guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate authority, as specified in the Bidding document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved: Provided that after the declaration of a bidder as successful the appeal may be filed only by a bidder who has participated in procurement proceedings: Provided further that in case a procuring entity evaluates the technical bids before the opening of the financial bids, an appeal related to the matter of financial bids may be filed only by a bidder whose technical bid is found to be acceptable.

2. The officer to whom an appeal is filed under Para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.
3. If the officer designated under Para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in Para (2), or if the bidder or prospective bidder or the procuring entity is aggrieved by the order passed by the first appellate authority, the bidder or prospective bidder or the procuring entity, as the case may be, may file a second appeal to second appellate authority specified in the bidding document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in Para (2) or of the date of receipt of the order passed by the first appellate authority, as the case may be.

4. Appeals not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the procuring entity relating to the following matters, namely:-

- (a) Determination of need of procurement;
- (b) Provisions limiting participation of bidders in the bid process;
- (c) The decision of whether or not to enter into negotiations;
- (d) Cancellation of a procurement process;
- (e) Applicability of the provisions of confidentiality.

5. Form of Appeals

- (a) An appeal under Para (1) or (3) above shall be in the annexed form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
- (b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee,
- (c) Every appeal may be presented to first appellate authority or second appellate authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

6. Fee for filing Appeal

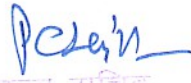
- (a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.
- (b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a scheduled bank in India payable in the name of appellate authority concerned.


राज्य सचिव
राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड
राज्य मुख्यालय, जयपुर

13
17

7. Procedure for disposal of Appeal

- (a) The first appellate authority or second appellate authority as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing
- (b) On the date fixed for hearing, the first appellate authority or second appellate authority, as the case may be shall-
- (i) Hear all the parties to appeal present before him; and
 - (ii) Peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.
- (c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the appellate authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.
- (d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the state public procurement portal.



राज्य सचिव
राजस्थान राज्य भारत स्काउट्स व गाइड्स
राज्य मुख्यालय, जयपुर

**Bidder Signature
With Stamp**

14
17

Annexure D : Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

- If there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;
- If there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected ; and
- If there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

(a) At the time of award of contract, the quantity of Goods, Works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(b) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(c) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the supplier.

3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.


राज्य सचिव
राजस्थान राज्य भारत स्काउट्स व गाइड्स
राज्य मुख्यालय, जयपुर

Bidder Signature
With Stamp

14
17

(चैक लिस्ट) : संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची

क्र. सं.	विवरण	संलग्न किये गये (हाँ/नहीं)	पृष्ठ संख्या
1.	सम्पूर्ण बोली प्रपत्र मय शर्तों के (निविदा दस्तावेज) हस्ताक्षर कर संलग्न है।		
2.	बोली शुल्क राशि रु. 500/- का बैंक ड्राफ्ट संलग्न है।		
3.	बोली प्रतिभूति राशि रु. 8,600/- का बैंक ड्राफ्ट संलग्न है।		
4.	फर्म के रजिस्ट्रेशन नम्बर की हस्ताक्षरित छांयाप्रति संलग्न है।		
5.	आयकर खाता संख्या (पैन नम्बर) की हस्ताक्षरित छांयाप्रति संलग्न है।		
6.	जी.एस.टी.आई.एन. पंजीयन क्रमांक की हस्ताक्षरित छांयाप्रति संलग्न है।		
7.	बिडर के बैंक खाते का विवरण (निरस्त चैक/पासबुक की छांयाप्रति) हस्ताक्षरित छांयाप्रति संलग्न है।		
8.	विनिर्माता/वास्तविक डीलर/अधिकृत विक्रेता आदि का घोषणा प्रपत्र एस.आर. प्ररूप-11 में राशि रु. 50/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर संलग्न है।		
9.	निविदा से सम्बन्धित अनुभव प्रमाण-पत्रों (कार्यानुभव) की हस्ताक्षरित छांयाप्रति संलग्न है।		
10.	निविदा से सम्बन्धित विगत तीन वित्तीय वर्षों 2019-20, 2020-21 व 2021-22 में से किसी एक वित्तीय वर्ष में निविदत्त अनुमानित लागत के 80 प्रतिशत के बराबर कार्य करने का सी.ए. द्वारा प्रमाणित टर्नओवर दस्तावेज (प्रमाण-पत्र) मय UDIN की प्रतिसंलग्न है।		
11.	नवीनतम कर बकाया नहीं हेतु अन्तिम त्रैमास (अप्रैल, 2022 से जून, 2022 तक) की जी.एस.टी. रिटर्न की प्रति (GSTR-1/GSTR-3B/Other) की हस्ताक्षरित प्रतिसंलग्न है।		
12.	अन्य प्रपत्र जो बोलीदाता संलग्न करना चाहते हैं।		

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर निविदादाता

मय मोहर

फर्म का नाम

फर्म के पत्र व्यवहार का पूरा पता

.....

.....

टेलीफोन नम्बर

P. Chaitan
राज्य सचिव
राजस्थान राज्य भारत स्काउट्स व गाइड्स
राज्य मुख्यालय, जयपुर

15
17



राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड राज्य मुख्यालय

जवाहरलाल नेहरू मार्ग, बजाज नगर, जयपुर - 302015 (राज.)

टेलीफोन नं. - 0141-2706830, 2941098 ई-मेल - rajscoutguide@yahoo.com



अनुमानित लागत राशि रु. 4,30,000/-

बोली शुल्क राशि रु. 500/-

बोली प्रतिभूति राशि रु. (दो प्रतिशत) 8,600/-

-:: निविदा प्रपत्र - ब (वित्तीय निविदा) ::-

भारत स्काउट व गाइड, राष्ट्रीय मुख्यालय, नई दिल्ली एवं राज्य मुख्यालय, जयपुर के तत्वाधान में ग्राम नीमली ब्राह्मणान, तहसील रोहत, जिला-पाली - 306421 (राजस्थान) में स्थित दिल्ली मुम्बई इण्डस्ट्रीयल कॉरीडोर पर आयोजित होने वाली 18वीं राष्ट्रीय स्काउट/गाइड जम्बूरी में एडवेंचर बेस हेतु रस्से, रस्सी व अन्य सामग्री (क्रय हेतु) हेतु निविदा :-

क्र. सं.	सामग्री (उपकरण) का विवरण	मात्रा	ईकाई	दर अंको में समस्त करें सहित	
				प्रति	कुल राशि
1	जूट रस्सा नया 2 इन्च मोटा बण्डल बना हुआ	2900 फीट	प्रति फीट		
2	जूट रस्सा नया 3 इन्च मोटा बण्डल बना हुआ	100 फीट	प्रति फीट		
3	जूट रस्सा 1.5" अथवा 40 एम.एम. मोटा बण्डल बना हुआ	200 फीट	प्रति फीट		
4	सफेद रंग की नई सूत की रस्सी 10 एम.एम. मोटी बण्डल	1230 किलो	प्रतिकिग्रा		
5	रस्सा सूत का 1 इन्च मोटा	290 किलो	प्रतिकिग्रा		
6	100 किलो वाली जूट की बोरियां खाली पुरानी साबुत कटी-फटी नहीं हो	600 नग	प्रतिनग		
7	सूतली 100 किलो	100 किलो	प्रतिकिग्रा		
8	पोली पोपलीन रस्सी 10 एम.एम.	12 बण्डल	प्रति बण्डल		
9	12 एम.एम. पीपीरोप	12 बण्डल	प्रति बण्डल		
10	बीओबी/आरओबी रोप	1000 फीट	प्रति फीट		
11	आरओबी रोप	400 फीट	प्रति फीट		
12	08 एम.एम. पीपी रोप	05 बण्डल	प्रति बण्डल		
13	जूट रस्सी मचान व स्ट्रक्चर बांधने के लिए	200 किलो	प्रतिकिग्रा		

Pstein

राज्य सचिव

राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड

राज्य मुख्यालय, जयपुर

16/17

क्र. सं.	सामग्री (उपकरण) का विवरण	मात्रा	ईकाई	दर अंको में	
				समस्त करों सहित	
				प्रति	कुल राशि
14	प्लास्टिक ब्लैक सीट नई 200 फीट लम्बी व 10 फीट चौड़ी	2000 वर्ग फीट	Per sqft		
15	तिरपाल 15 फीट लम्बी व 10 फीट चौड़ी	150 वर्ग फीट	Per sqft		

मैंने/हमने निविदा की समस्त शर्तें पढ़ ली हैं और मैं/हम इन्हें मानने के लिए बाध्य हूँ, मैं/हम उपरोक्तानुसार निविदा हेतु दी गई दरों पर मेरी/हमारी फर्म द्वारा कार्य करने को तैयार/सहमत हूँ। इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी/हमारी होगी।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर निविदादाता

मय मोहर

फर्म का नाम

फर्म के पत्र व्यवहार का पूरा पता

.....

.....

टेलीफोन नम्बर



राज्य सचिव

राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड

राज्य मुख्यालय, जयपुर

17/17